साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 48 | प्रति सोमवार इंदौर, 01 जुलाई से 07 जुलाई 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

विश्व में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत समाप्त

पेट्रो क्रूड क्रय करने में सभी देशों की मुद्रा होगी मान्य

अरब ने पेट्रो क्रूड क्रय करने में डॉलर में भूगतान का समझौता किया समाप्त

विश्व पर संकर प्रजाति के अमेरिका की गुंडागर्दी, दादागिरी और अपना माल बेचने के भय, आतंकवाद फैलाने, ना मानने पर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। और हर तरह से भी अमेरिकी प्रतिबंधों षड्यंत्रों से बचने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में दुनिया के देशों कोअपने देश की जनता, उद्योगों व उन्नति के पहिए को चलायमान रखने के लिए आवश्यक पेट्रो क्रूड को अरब देशऑन या ओपेक से खरीदने के लिए अमेरिकी मुद्रा डॉलर में भुगतान करना पड़ता थाअब अरब ने हीं अमेरिका के पेट्रो डॉलर समझौते को अमेरिका से मुक्ति पाने और उस पर निर्भरता घटाने रद्द कर दिया है। अब सभी पेट्रोल क्रय करने वाले राष्ट्र अब अपनी मुद्रा में भुगतान करने के स्वतंत्र हैं।

क्या पेट्रोडॉलर का अंत निकट है?

जैसे-जैसे ब्रिक्स समूह के देश और मध्य पूर्व और एशिया सहित क्षेत्र सीमा पार भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ा रहे हैं, यह धारणा बढ़ रही है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त में डॉलर का महत्व कम हो रहा है, विशेष रूप से वैश्विक तेल बाजारों और पेट्रोडॉलर के उपयोग में।

पेट्रोडॉलर वास्तव में क्या है? संक्षेप में, यह सऊदी अरब द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को तेल की बिक्री से प्राप्त डॉलर राजस्व का उपयोग अमेरिकी खजाने को खरीदने के लिए करने की प्रतिबद्धता है। लेकिन इतिहास अधिक जटिल है।

1974 में अमेरिका और सऊदी अरब

आइए निक्सन प्रशासन पर एक नज़र डालें। वियतनाम में चल रहे युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च मुद्रास्फीति और बड़े चालू खाता घाटे से घिरा हुआ था, जिससे डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था और अमेरिकी स्वर्ण भंडार पर संकट मंडरा रहा था। 1971 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को समाप्त कर दिया, जो निश्चित विनिमय दरों की ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का मुख्य आधार था। 1973 में प्रमुख मुद्राएँ एक दूसरे के विरुद्ध तैरने लगीं। फिर उस गिरावट में तेल का झटका आया, जब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने तेल उत्पादन में कटौती की और योम किप्पुर युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया।

जब वाटरगेट की सुनवाई अपने अंतिम चरण में थी, तब आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में निक्सन प्रशासन ने एक राजनयिक मिशन शुरू किया, जो सऊदी अरब के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए केंद्रीय रहा है। रियाद को तेल की बिक्री के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में डॉलर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, (और इस तरह उन डॉलर को अमेरिकी राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने में मदद करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड बाजारों में वापस लाना), वाशिंगटन ने सऊदी अरब को सैन्य उपकरण आपूर्ति करने और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का वादा किया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में उथल-पुथल और अस्थिरता के बावजूद, इस सौदे ने दिखाया कि इसने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने की शक्ति बरकरार रखी है। डॉलर की मांग को स्थिर रखने के अलावा, इस समझौते ने तेल और कमोडिटी ट्रेडिंग में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी के लिए मांग का एक स्थिर स्रोत बनाया। इसने दुनिया के प्रमुख रिजर्व, वित्तपोषण और लेन-देन मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति को मजबूत करने में मदद की।

(शेष पेज 7 पर)

मुख्यमंत्री बदला फिर भी भर्तीयां व पदोन्नतियां नहीं

नियमित करो, बंद करो लूट का प्रभार से प्रभार का खेल

18 साल में सभी विभागों को कर दिया खोखला, कर्मचारी अधिकारियों का शोषण बंद करो, संविदा व ठेके पर काम की अपेक्षा नियमित भर्तीयां करो

मध्य प्रदेश में पिछले 30 सालों से सभी विभागों में नियमित भर्तीयां नहीं की जा रही हैं। जिससे सभी मंत्रालय के शासकीय विभागों में शिक्षा पुलिस विभाग से लेकर लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मत्स्य, रेशम, श्रम विभाग, न्यायालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, महिला बाल विकास, वन, कृषि, उद्यानिकी, गृह निर्माण मंडल, ऊर्जा विभाग की सभी कंपनियों मैं लाइनमैन और सहायक से लेकर, यंत्रियों, लिपिक वर्ग तक, आदिम व अनुसूचित जाति जन जाति, पिछड़ा वर्ग, आबकारी, वाणिज्य कर, पंजीयन, खनन, खाद्य एवं औषधि, स्वास्थ्य, राजस्व, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकीय आदि विभागों में मैं लगभग 5 लाख से ज्यादा अधिकारियों इंजीनियर वैज्ञानिक शिक्षक कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर भृत्य व मजदूर स्तर तक के कर्मचारियों की आवश्यकता है। परंतु नियमित भर्तियां नहीं की जा रही। पिछले 30 सालों से विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर की पदों पर अस्थाई भारतीय की जा रही हैं और पहले जिन कंप्यूटर ऑपरेटर को सीधे ही विभागों में उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था। उन सबको भी सेड मैप के बन जाने जो की गैर सरकारी संगठन है जिसे सरकार ने स्वयं माना की सेडमेप गैर सरकारी है।

(शेष पेज 6 पर)

मप्र सरकार देश व विश्व में सबसे महंगा पेट्रोल, शराब, बिजली बेच रही

पंजीयन परिवहन व अन्य शुल्क 10 गुना ज्यादा

सित. 23 से कार्यों के भुगतान के लिए नहीं है पैसा, बड़े-2 प्रोजेक्ट में मोटी दलाली के लिए 2 से 10 गुना डीपीआर व अरबों रू रोज विज्ञापनों पर खर्च से अर्थव्यवस्था घाटे में

मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज की सरकार के जाने के बाद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के बनने से लगा था कि एक शिक्षित व्यक्ति व शिक्षण संस्थान से जुड़ा व्यक्ति मुखिया बनने के बाद स्थिति में सुधार आएगा परंतु जिस मूढ़ मोदी ने उसका चयन करके बैठाया था। उसका उद्देश्य ही था, कि अपने तरीके से हर कदम पर लूट और अपने गुजरातियों ठेकेदार कंपनियां अडानी अंबानी आदि को उपकृत कर पूरे प्रदेश की सरकार व प्रशासन को चलाया जाए। सन 2014 के बाद प्रदेश के अधिकांश विभागों में जिसमें लोक निर्माण में सड़कों भवनों पुलों आदि का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय में वर्तमान मेंजल से जीवन मिशन के अंतर्गत टंकियां बनाना पाइप लाइन बिछाना वह ग्रामीण और शहरीय आबादी के क्षेत्र में घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कार्य, नर्मदा घाटी व जल संसाधन विभाग में कृषि की सिंचाई के लिए बांधों नहरों के निर्माण कार्य के अधिकांश ठेके पूरे प्रदेश भर में जो अधिकांश लिफ्ट इरीगेशन के होने के साथ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो हजारों करोड़ की हैं। गृह निर्माण मंडल, पुलिस गृह निर्माण से लेकर प्रदेश के अधिकांश निगम पालिकाओं परिषदों आदि में अधिकांश ठेकेदारी का कार्य जालसाज हरामखोर गुजराती ठेकेदार ही कर रहे हैं।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

आत्महत्या और इसकी रोकथाम

भारत में तत्काल आवश्यकता लक्ष्मी विजयकुमार लेखक जानकारी कॉपीराइट और लाइसेंस जानकारी PMC अस्वीकरण आत्महत्या भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश में हर साल एक लाख (एक सौ हज़ार) से ज़्यादा लोगों की जान आत्महत्या के कारण चली जाती है। पिछले दो दशकों में, आत्महत्या की दर 7.9 से बढ़कर 10.3 प्रति 100,000 हो गई है। देश के भीतर आत्महत्या की दरों में व्यापक भिन्नता है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में आत्महत्या की दर > 15 है जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू और कश्मीर के उत्तरी राज्यों में आत्महत्या की दर < 3 है। यह परिवर्तनशील पैटर्न पिछले बीस वर्षों से स्थिर है। उच्च साक्षरता, बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली, कम बाहरी आक्रामकता, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति और उच्च अपेक्षाएँ दक्षिणी राज्यों में उच्च आत्महत्या दरों के लिए संभावित स्पष्टीकरण हैं। भारत में आत्महत्या करने वालों में से अधिकांश (37.8%) 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। यह तथ्य कि भारत में 71% आत्महत्याएं 44 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा की जाती हैं, हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ डालता है। युवा पुरुषों और महिलाओं की लगभग समान आत्महत्या दरें

2.और लगातार संकीर्ण पुरुषः महिला अनुपात 1.4: 1 दर्शाता है कि पश्चिमी समकक्षों की तुलना में अधिक भारतीय महिलाएं आत्महत्या से मरती हैं। जहर (36.6%), फांसी (32.1%) और आत्मदाह (7.9%) आत्महत्या करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीके थे। 1. ग्रामीण तमिलनाडु में दो बड़े महामारी विज्ञान मौखिक शव परीक्षण अध्ययनों से पता चलता है कि वार्षिक आत्महत्या दर आधिकारिक दर से छह से नौ गुना अधिक है।

3,4. यदि इन आंकड़ों का अनुमान लगाया जाए, तो यह पता चलता है कि भारत में हर साल कम से कम आधा मिलियन आत्महत्याएं होती हैं। इस प्रकार, आत्महत्या एक प्रमुख सार्वजनिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हालाँकि आत्महत्या एक बहुत ही व्यक्तिगत और व्यक्तिगत कार्य है, लेकिन आत्मघाती व्यवहार कई व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जब से एस्क्विरोल ने लिखा कि 'आत्महत्या करने वाले सभी लोग पागल हैं' और दुर्खीम ने प्रस्तावित किया कि आत्महत्या सामाजिक / सामाजिक स्थितियों का परिणाम है, तब से आत्महत्या के कारणों में व्यक्तिगत भेद्यता बनाम सामाजिक तनाव की बहस ने आत्महत्या पर हमारे विचारों को विभाजित कर दिया है। आत्महत्या को एक बहुआयामी, बहुक्रियात्मक अस्वस्थता के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। हमारे देश में आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है और इसलिए, मानसिक विकार को पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक कुव्यवस्था आदि के साथ समान वैचारिक दर्जा दिया जाता है।

5. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 43% आत्महत्याओं के लिए आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं है, जबकि बीमारी और पारिवारिक समस्याएं लगभग 44% आत्महत्याओं में योगदान करती हैं। तलाक, दहेज, प्रेम संबंध, विवाह रद्द होना या न हो पाना (भारत में तय विवाह की व्यवस्था के अनुसार), नाजायज गर्भधारण, विवाहेतर संबंध और विवाह के मुद्दे से जुड़े ऐसे संघर्ष, विशेष रूप से भारत में महिलाओं की आत्महत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक परेशान करने वाली विशेषता आत्महत्या के समझौते और पारिवारिक आत्महत्याओं की लगातार घटना है, जो सामाजिक कारणों से अधिक होती हैं और इसे पुरातन सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा पर जनसंख्या-आधारित अध्ययन में, यह पाया गया कि 64% महिलाओं में घरेलू हिंसा और आत्महत्या के विचार के बीच महत्वपूर्ण संबंध था।

6. बैंगलोर में किए गए एक अध्ययन में घरेलू हिंसा को भी आत्महत्या का एक प्रमुख जोखिम कारक पाया गया।ड7. जनसंख्या-आधारित अध्ययन भारत के विभिन्न शहरों में किया गया है, हालांकि बैंगलोर अध्ययन एकमात्र मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण अध्ययन है

मानसिक विकार और आत्महत्या

मानसिक विकार आत्महत्या के कारणों के मैट्रिक्स में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अधिकांश अध्ययनों में पाया गया है कि आत्महत्या से मरने वाले लगभग 90% लोग मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं।

9. आत्महत्या से मरने वाले लोगों के मनोवैज्ञानिक निदान का विशेष रूप से अध्ययन करने वाली प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है (n = 15629)। ऐसी अधिकांश रिपोर्ट (82.2%) यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आती हैं, जबकि विकासशील देशों से मात्र 1.3% रिपोर्ट आती हैं।

8. भारत में चेन्नई 10. और बैंगलोर 7. में मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण तकनीक का उपयोग करके दो केस कंट्रोल अध्ययन किए गए हैं। आत्महत्या से मरने वालों में से, चेन्नई में 88% और बैंगलोर में 43% में निदान योग्य मानसिक विकार था। हालाँकि, बैंगलोर अध्ययन में नैदानिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

अनेक विशेषज्ञों ने पाया है कि आत्महत्या से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निदान भावात्मक विकार हैं। चेन्नई में, 25% आत्महत्याएँ मनोदशा विकारों के कारण पाई गईं। हालांकि, जब अवसादग्रस्त मनोदशा के साथ समायोजन विकार वाले आत्महत्या के मामलों को भी गिना गया तो आत्महत्या की दर बढ़कर 35% हो गई। आत्महत्या में अवसाद की महत्वपूर्ण और कारण भूमिका की भारत में सीमित वैधता

है। यहां तक कि जो लोग अवसादग्रस्त थे, वे भी अल्प अवधि के लिए अवसादग्रस्त थे और उनमें केवल हल्के से मध्यम लक्षण थे। अधिकांश मामलों में अवसाद के अपने पहले प्रकरण के दौरान ही आत्महत्या कर ली और अवसादग्रस्त आत्महत्याओं में से 60% से अधिक में केवल हल्के से मध्यम अवसाद था।

10. हालांकि भारत में सामाजिक रूप से शराब पीना जीवन का तरीका नहीं है, लेकिन भारत में आत्महत्या में शराब की लत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 35% आत्महत्याओं में शराब पर निर्भरता और दुरुपयोग पाया गया। लगभग 30-50% पुरुष आत्महत्या करते समय शराब के प्रभाव में थे और कई पत्नियों को उनके शराबी पतियों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। शराब की लत के लिए ऑड्स अनुपात (ओआर) चेन्नई में 8.25 (विश्वास अंतरालः सीआई 2.9-3.2) था 10. और बैंगलोर में 4.49 (सीआई 2.0-6.8) 7.। भारत में लगभग 8% आत्महत्याएं सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। श्रीनिवासन और थारा ने पाया कि सिज़ोफ्रेनिक आत्महत्याओं के लिए पुरुष से महिला अनुपात कमोबेश बराबर है। 11. हालांकि चेन्नई अध्ययन में 88% आत्महत्याओं में निदान योग्य मानसिक विकार पाए गए, केवल 10% ने कभी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को देखा था। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में केवल 4.74% आत्महत्याएं मानसिक विकारों के कारण होती हैं। पूर्ण आत्महत्याओं में से 20% में व्यक्तित्व विकार पाया गया। ओआर 9.5 (सीआई 2.29-84.11) था। क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार 12ङ आत्महत्याओं में पाया गया। आत्महत्या के केवल 30% मामलों में ही सह-रुग्णता का निदान पाया गया। 10. पिछले आत्महत्या के प्रयासों का इतिहास बाद में आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाता है। पिछले आत्महत्या प्रयासों के लिए OR चेन्नई में 5.2 (CI 1.96-17.34) और बैंगलोर में 42.62 (5.78-313.88) था।

आत्महत्याओं के समूह

मीडिया कभी-कभी 'आत्महत्या समूहों' को बहुत ज़्यादा प्रचारित करता है - आत्महत्याओं की एक श्रृंखला जो मुख्य रूप से कम समय में एक छोटे से क्षेत्र में युवाओं के बीच होती है। इनका संक्रामक प्रभाव होता है, खासकर तब जब उन्हें ग्लैमराइज़ किया जाता है, जिससे नकल या 'नकल आत्महत्या' को बढ़ावा मिलता है। यह घटना भारत में कई मौकों पर देखी गई है, खासकर किसी सेलिब्रिटी की मौत के बाद, अक्सर किसी फिल्म स्टार या राजनेता की। मीडिया द्वारा इन आत्महत्याओं को दिए गए व्यापक प्रचार के कारण इसी तरह की आत्महत्याएँ हुई हैं। फिल्मों में दिखाए गए नकल के तरीके भी असामान्य नहीं हैं। यह एक गंभीर समस्या है, खासकर भारत में जहाँ फिल्मी सितारों को एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है और उनका खास तौर पर युवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो अक्सर उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं।

सरकार में रोजगार के लिए 27% पदों को आरक्षित करने की मंडल आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन ने छात्र समुदाय में अशांति पैदा की और एक छात्र ने इस तरह के आरक्षण के खिलाफ़ विरोध कर रहे लोगों के एक समूह के सामने आत्मदाह कर लिया। इसे मीडिया द्वारा सनसनीखेज और व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। देश भर में छात्रों द्वारा आत्मदाह (n = 31) की बाढ़ आ गई थी। इन नकलची आत्महत्याओं ने लोगों में आक्रोश पैदा किया और इसे उस समय सत्ता में आई सरकार के पतन के कारणों में से एक माना गया।

सामाजिक परिवर्तन

आधुनिकीकरण के प्रभावों ने, विशेष रूप से भारत में, लोगों के जीवन के सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-दार्शनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए हैं, जिससे जीवन में तनाव बहुत बढ़ गया है, जिससे आत्महत्या की दर में काफी वृद्धि हुई है। 13. भारत में, युवा वयस्कों में आत्महत्या की उच्च दर अधिक सामाजिक-आर्थिक तनावों से जुड़ी हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण के बाद नौकरी की सुरक्षा, आय में भारी असमानता और नए सामाजिक रूप से बदले हुए वातावरण में भूमिका दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का कारण बनी है। संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना जिसने पहले भावनात्मक समर्थन और स्थिरता प्रदान की थी, उसे भी भारत में आत्महत्याओं में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है।

धार्मिकता

धर्म व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य करता है। अक्सर बहस का विषय यह है कि क्या धर्म द्वारा प्रस्तुत सामाजिक नेटवर्क सुरक्षात्मक है या यह व्यक्ति की आस्था है। चेन्नई में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ईश्वर में विश्वास की कमी के लिए OR 6.8 (CI 2.88-19.69) था। 15.आत्महत्या करने वालों में ईश्वर में कम आस्था थी, उन्होंने अपना धार्मिक जुड़ाव बदल लिया और शायद ही कभी पूजा स्थलों पर गए। आत्महत्या से तीन महीने पहले ग्यारह प्रतिशत लोगों ने अपना विश्वास खो दिया था। गुरुराज एट अल ने यह भी पाया कि धार्मिक विश्वास की कमी एक जोखिम कारक थी (OR 19.18, CI 4.17-10.37)। 7. कानूनी मुद्दे भारत में, आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में कहा गया है कि 'जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए कोई भी कार्य करता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा'। हालाँकि, कानूनी तरीकों से आत्महत्या को रोकने के लिए कानून का उद्देश्य उल्टा साबित हुआ है। आत्महत्या का प्रयास करने वालों को आपातकालीन देखभाल से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि कई अस्पताल और चिकित्सक कानूनी झंझटों के डर से आवश्यक उपचार प्रदान करने में झिझकते हैं। आत्महत्या के प्रयासों का वास्तविक डेटा पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस और अदालतों में उलझने से बचने के लिए कई प्रयासों को आकस्मिक बताया जाता है।

आत्महत्या की रोकथाम

यह विचार कि आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता, स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच भी आम है। कई मान्यताएँ इस नकारात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या कर सकती हैं। इनमें से मुख्य यह है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत मामला है जिसे व्यक्ति को ही तय करना चाहिए। एक और मान्यता यह है कि आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसके प्रमुख निर्धारक सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हैं जैसे कि बेरोज़गारी जिस पर व्यक्ति का अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। हालाँकि, आत्मघाती व्यवहार में लिप्त अधिकांश लोगों के लिए, संभवतः समस्याओं का एक उपयुक्त वैकल्पिक समाधान है। आत्महत्या अक्सर एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान होती है। ब्राज़ेक और है गर्टी केड 16. ढांचे ने आत्महत्या रोकथाम हस्तक्षेप को सार्वभौमिक, चयनात्मक या उनके लक्षित समूहों को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसके आधार पर संकेतित के रूप में वर्गीकृत किया। सार्वभौमिक हस्तक्षेप पूरी आबादी को लक्षित करते हैं जिसका उद्देश्य पूरी आबादी में समीपस्थ या दूरस्थ जोखिम कारकों को अनुकूल रूप से स्थानांतरित करना है। चयनात्मक हस्तक्षेप उपसमूहों को लक्षित करते हैं जिनके सदस्य अभी तक आत्मघाती व्यवहार प्रकट नहीं कर रहे हैं लेकिन जोखिम कारक प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें भविष्य में ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। संकेतित हस्तक्षेप उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो पहले से ही आत्मघाती विचार या व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर चुके हैं। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भारत संक्रामक रोगों, कुपोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और इसलिए, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में आत्महत्या को कम प्राथमिकता दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ देश की ज़रूरतों के लिए अपर्याप्त हैं। एक अरब से ज़्यादा की आबादी के लिए, केवल लगभग 3,500 मनोचिकित्सक हैं। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उभरती पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण सामाजिक उथल-पुथल और संकट पैदा हो रहे हैं। कम होते पारंपरिक सहायता तंत्र लोगों को आत्मघाती व्यवहार के प्रति कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए, बाहरी भावनात्मक समर्थन की ज़रूरत उभर रही है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा की कमी के साथ समस्या की गंभीरता ने आत्महत्या की रोकथाम के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के उद्भव को जन्म दिया है। इन गैर सरकारी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों से दोस्ती करके उन्हें सहायता प्रदान करना है।

जनधन मोटी दलाली व हवाई सपने पूरे करने, मीडिया में उड़ाओ

3.9 लाख करोड़ के साथ 88540 करोड़ का नया कर्ज घी पीने

बकवास: किसानों को निशुल्क बीज, सौ यूनिट निशुल्क बिजली बांटने, कृषि पंपों पर अनुदान पर खर्च। मीडिया में भ्रष्टाचार छुपाने 40 हजार करोड़, बड़ी परियोजनाएं दलाली खाने में चाहिये। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल गैस शराब परिवहन शुल्क पंजीयन का पैसा कहां जा रहा?

प्रदेश में घोर भ्रष्ट जालसाज शिक्षा, भू, कॉलोनी, शराब, ईंट भट्टा आदि माफिया के नाम से कुख्यात मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उसकी उपरोक्त विशेषताएं ही थीं। जिससे मोटी वसूली कर घोर भ्रष्ट जालसाज मूढ़ मोदी ने पूर्व के शिक्षा मंत्री मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। 18 साल तक प्रदेश के शिवराज के मुख्यमंत्री रहते हुए व्यापम घोटाला इसी के कार्यकाल में हुआ था। उज्जैन की सिंहस्थ क्षेत्र की 38 एकड़ भूमि पर कब्जे का मामला भी विधानसभा में उठा था। अब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हैऔर पूरे प्रदेश के सारे बिल्डरों भू कॉलोनी माफिया से वसूली के लिए न केवल प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों पर पुरानी से पुरानी कॉलोनीयों का अवैध बता कर वसूली का दवाब डालने के साथ, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर की एंटी इवेजन की टीमों को भी बिल्डर भू व कॉलोनी माफियाओं पर छापे डलवा कर उनको घेर कर वैध अवैध मोटी वसूली करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रदेश में देश व दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल गैस शराब बिजली बैंची जा रही है। उससे भी प्रतिदिन मोटी सैकड़ों करोड़ की कमाई हो रही है। केंद्र सरकार की नियमों और गाइडलाइन के विपरीत कई गुना ज्यादा पंजीयन, परिवहन, सरकारी शिक्षण शुल्क, गौड़ व मुख्य खनिजों के खनन का शुल्क वसूला जा रहा है। बेशक खनन के मामले में 50 से 70% तक अवैध खनन करवा कर अपने खनन माफियाओं को भी संरक्षण देकर मोटी वसूली भी की जा रही है। इसके बाद में भी सरकार के पास धन नहीं है। और सरकार 3.9 लाख का करोड़ का कर्ज होने के बाद में 88540 करोड़ का जो कर्ज ले रही है। यथार्थ मेंजन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं वरन बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जिसमें अधिकांश 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जल संसाधन व नर्मदा घाटी की हैं। जिसमें अकेले 35000 करोड़ की बेतवा लिंक परियोजना है। 1970 सेजल संसाधन विभाग ने लिफ्ट परियोजनाओं की निर्माण लागत के साथ भारी भरकम बिजली खर्च, उसके बाद उसके भारी भरकम रखरखाव खर्च के कारण बंद कर दी थी परंतु मोटे कमीशन के लालच के चलते और विश्व बैंक के साथ एशियाई विकास बैंक के मोटे कर्ज के चलते पुनः हजारों करोड़ की लिफ्ट इरीगेशन और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के नाम से पुनः शुरू कर दी गई। जिन्हें धन के अभाव मेंलंबित किया जा सकता था परंतु कर्ज लेकर घी पीने की आदत तो शिवराज के बाद गुजराती मूढ़ लालची मोदी ने अपनी मोटी वसूली के लिए भाजपा शासित राज्यों में पक्की व मजबूत कर दी। प्रदेश की जनता पर हजारों करोड़ की मोटी वसूली करने के बाद में भी जनता पर मोटा कर्ज लादने और 1% मासिक ब्याज के हिसाब से लगभग 40 हजार करोड़ के ब्याज का खर्च भी इसीलिए लादा जा रहा है। ताकिमोटी कमाई की जा सके जबकि प्रदेश के राजस्व मेंइतनी आए हो रही है जिससे मध्य प्रदेश सरकार की खर्चा आसानी से चलाया जा सकते हैंके विपरीत प्रदेश सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो लाडली बहन योजना शुरू की थी उसे पर वार्षिक 18000 करोड रुपए का खर्च आ रहा है दूसरी तरफ जैसा कहा जा रहा है कि किसानों को मुफ्त बीज दिए जा रहे हैं बिल्कुल बकवास कर रहे हैं बेशक किसानों को मुक्त भी देने के नाम से वह पैसा जिले के उपसंचालकों से लेकर संभागीय और कृषि व उद्यानिकी के मुख्यालय में बैठे संचालक प्रधान सचिव कृषि व उद्यानिकी मंत्री मुख्यमंत्री ऊपर के ऊपर हीहजम कर रहे हैं क्योंकि मेरी अनेकों किसानों से व कृषि विज्ञान की विभाग के अधिकारियों से बात होने के बाद में भी पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं बतायाकी बी मुफ्त दिया जा रहा है। उल्टे ही किसानों के अनेकों प्रकार के खाद बीज कीटनाशकों पर दिए जाने वाले सभी प्रकार के अनुदान खत्म कर दिए गए के साथ ही सबकी बाजार की कीमत भी दो से 5 गुनी हो चुकी है। जबकि कृषि उपजो के उत्पादन लागत का बाजार मूल्य कृषकों को उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा बेशक थोड़ी बहुत अनुदान की राशि सरकार ने जो गेहूं धान आदि की सरकारी खरीद पर अवश्य दिया और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की दलील में जनता को सौ यूनिट बिजली फ्री देने के षड्यंत्र में भी पिछले 3 सालों से बिजली का कागज पर छपा हुआ बिल ही नहीं दिया जा रहा। और मोबाइल पर बिल देने का षड़यंत्र ही इसीलिए ही किया गया ताकि कोई भी उपभोक्ता अपने मीटर से बिजली के बिल पर दी हुई उनकी खपत का आकलन ही नहीं कर सके और उसे मालूम ही नहीं चले कि वास्तविकता में उसने कितनी बिजली खपत की। किसी का भी बिल 250 300 यूनिट से कम नहीं आ रहा। 300 वर्ग फीट के मकान में जहां एक पंखा 250 वाट का 1-2 एल ईडी बल्ब 12 15 वाट के महीने भर जलते हैं उनके भी बिल गांवों से लेकर शहरों तक अब 500 700 से लेकर ढाई हजार रुपए महीने तक आने लगे हैंतो हरामखोर जलसा जो 100 यूनिट बिजली बिल पर किसको अनुदान दे रहे हो बल्कि उल्टे ही स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर 3 से 10 गुनी ज्यादा बिजली खपत दिखाकरउल्टे ही मोती वसूली की जा रही है।

अपनी मोटी वसूली वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे लाभ के लिए प्रदेश में शुरू किए गए। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर हजारों करोड़ की मनचाही मनमानी दरों की निविदायें निकाल, पुराने बाजरो उद्योग धंधों को उजाड़ने गलियों बाजारों को तोड़ा-फोड़ा और जिन जाहिल गैर तकनीकी एडीएम एसडीएम निगमायुक्तों को प्रदेश के बड़े महानगरों उज्जैन इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर आदि में उन स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक बना दिया गया। जिस पर जनता का हजारों करोड़ खर्च किया गयादूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के नाम परजनता पर 10 गुना से ज्यादाअक्षों का शुल्क कचरा शुल्कसंपत्ति कर बढ़ा लूटा जा रहा है। जो पिछले 7 सालों में निरर्थक और बकवास सिद्ध हुआ इन सभी शहरों की न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भीसारे स्मार्ट सिटी लिमिटेड को तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखकर शिक्षा के उत्थान को देख, करने के नाम पर एक तरफ पेट्रोल डीजल गैसव अन्य सेवाओं पर शिक्षा सेस ठोकने के साथ उस धन से . सीएम राजेश स्कूलों में भीचार से 10 गुना की डीपीआर बनाकरभवन बनाने के नाम परभी एक तरफ मोटा धन हड़प जा रहा है तो उसका भार भी पुलिस सरकार के वित्त व्यवस्था पर पड़ रहा है। जबकि शिक्षा सुधार के लिए जरूरत यह थी की सरकारी प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विद्यालयों में उच्च शिक्षित नियमित शिक्षा व बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति समर्पित शिक्षकों की भारतीय की जाती पुराने शिक्षकों कोउचित तरह से प्रशिक्षण दिया जाताऔरबच्चों के उद्योग भविष्य के लिएअच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती थीपर उसकी आड़ मेंतोसरकार की मोटिवेशन की इच्छा ही ज्यादा काम कर रही है।

दूसरी तरफ हवाई एम्बुलेंस, हवाई तीर्थ दर्शन योजनाके नाम पर अपनी आंतरिक इच्छाओं की उड़ान भरने हवाई जहाज का सपना पूरा करने अपने व परिवार मित्रों के लिये उपयोग करने, जनधन को अपने बाप की जागीर समझने और अपने मित्रों अधिकारियों, पार्टी के कार्य कर्ताओं, अंतरंग वहिरंग सहेलियों को घुमाने फिराने के, जनता व अन्य सेवकों को मालूम ना पड़े अपने काले धन को अल्लाह ने ले जानेहवाला करने भेजना निवेदिता करने की स्टूडेंट को पूरा करने के लिए जो हवाई एंबुलेंस होती थी यात्रा का नाटक किया जा रहा है और जनता का थन विनियोजित किया जा रहा है। वह सब कहां से हो रहा है? यथार्थ में कच्छजनधन की योजनाओं को पूरा करने नहीं अपने सपनों को पूरा करने और जनता पर उसका भार लादने के लिए लिया जा रहा है। जिसकी कदापि जरूरत नहीं थी। वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार को इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। इसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार और 15 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने की योजना है। इसके बाद ही लाड़ली बहना जैसी फ्लैगशिप योजनाएं चल पाएंगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था।

इस बार 38% ज्यादा कर्ज लेगी सरकार

यानी सरकार इस बार 38% ज्यादा कर्ज लेगी। हालांकि, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का स्पष्ट कहना है कि कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जाता है, जिसका भुगतान भी समय से किया जाता है। लेकिन चिंता यह भी है कि इस साल बजट अनुमान 3.50 लाख करोड़ रुपए है। फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने यदि 88000 करोड़ का कर्ज लिया तो कुल कर्ज पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा।

ये हैं लोन लेने के कारण

लाड़ली बहना जैसी योजनाओं के लिए हर साल 25 हजार करोड़ रु. चाहिए, फ्री बीज योजनाएं लाड़ली बहना योजना में हर साल 18 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे। इसके अलावा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने में 5,500 करोड़ रुपए, कृषि पंपों पर सब्सिडी पर 17 हजार करोड़ रुपए और 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए। फ्री बीज मुफ्त योजनाओं का खर्चा हर साल 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें लाड़ली बहना का 12वीं किस्त के भुगतान में 16 हजार करोड़ रुपए पार कर गया है। कर्मचारियों के वेतन-भत्ते साल 2021-22 में कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्चा 59,662 करोड़ रुपए था, जो बजट का 24.78% था। साल 2023-24 में यह 82,838 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बजट का 27.43% है। जीपीएफ में भी नुकसान वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों के जीपीएफ में 4,949 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि भुगतान 5,563 करोड़ रुपए का हुआ। यानी 614 करोड़ रु. ज्यादा का भुगतान हुआ। अभी सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है। यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। ऐसे में बजट अनुमान 3.40 लाख करोड़ रुपए की खाई 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कम करना होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कसा तंज

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024 25 के लिए 88 हजार 450 करोड़ रुपए का कर्ज़ लेने जा रही है. इससे पहले मध्य प्रदेश पर 3.50 लाख करोड रुपए से ज्यादा कर्ज लिया गया था जिसे सरकार अभी तक चुका नहीं पाई है फिलहाल प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश 4.48 लाख करोड रुपए का कर्ज़ चढ़ जाएगा कर्ज में दबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि उत्कर्ष का ब्याज भरने के लिए उधार लेना पड़ रहा है यह अनुचित आर्थिक नीतियों और अपरिक्व के निर्णयो का परिणाम है।

साप्ताहिक समय माया

ग्रीन हाऊस में पोली फिल्मस का महत्व

हरित गृह खेती को औद्योगिक रूप में भारत देश में शुरूआत 1989 में हुई थी और आज लगभग 22 वर्ष पश्चात हरित गृह के ढांचे जलवायु नियत्रंण, फसलों की समय क्रियाए, तुड़ाई, तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन सिचाई पद्धति एवं फर्टीगेंशन इत्यादि ने स्थायित्व रूप धारण कर लिया है फिर भी नई तकनीक एंव नवाचार के सर्द्धभ में हरित गृह इंडस्ट्री के दरवाजे आज भी खुले हुए है ताकि इन्हे अपनाकर हरित गृह में लगाये जाने वाली फसलों की गुणवता एवं मात्रा में बढ़ोत्तरी की जा सके।

पोली हाऊस की ढाँचे की मजबूती के लिए गेलवेनाइजड आयरतन की बनी पाईपो का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसकी आयु 15-20 वर्ष तक ऑकी गई है। वैसे ही एक अच्छी आयात की गई। पोली थीन फिल्म की भी आयु 3 वर्ष ऑकी गई है। मुख्य रूप से पैरा बैगनी विकिरण, थर्मल डीग्रेडेश, फोटो ऑकसडेसन एंव फसल सरंक्षण के काम में लिए जाने वाले रसायनिक उत्पाद, चार कारक पोलीफिल्म की आयु को प्रभावित करती है। कुछ कृषकों द्वारा गर्मियों के मौसम में पोलीथीन फिल्म के ऊपरी तरफ (बाहर) सफेद चूने की पुताई फुट पम्प द्वारा की जाती है। जिससे प्रकाश की तीव्रता में तो कमी आती है परन्तु पोली फिल्म की आयु पर विपरित असर पड़ता है। अतः कृषकों को इस प्रकार की तकनीकी नही अपनानी चाहिए।

पोली फिल्म के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी आमतौर में उन कृषकों के लिए जरूरी है। जो हरित गृह (पोली हाऊस) लगाना चाहते है या फिर हरित गृह सम्बंधित व्यवसाय में दिलचस्पी रखते है। कृषक के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाजार से विभिन्न गुणवता वाली पोली फिल्म उपलब्ध है और उनमें में कौन सी प्रकार की पोली फिल्म उसकी फसल एंव उसके क्षेत्र की जलवायु को देखते हुए उपयुक्त है।

आम तौर पर प्रत्येक पोली थीन जिसका उपयोग पोली हाऊस बनाने के लिए किया जात है 200 माइक्रोन मोटाई वाली, पैरा बैगनी किरणों को रोकने वाली इन फ्रा रेड थर्मिक, धूल मिट्टी प्रति रोधी, बूंद प्रतिरोधी जैसे महत्वपूर्ण गुणों के समावेश वाली होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे की ज्यादातर देश के विभिन्न क्षेत्रो में दिन का तापमान अत्यधिक रहता है और हरित गृह में तापमान को कम करने की जरूरत महसूस की जाती है ऐसे में बुद्धिमता इसी में है कि इनफ्रा परावर्तित ठण्डी झील्ली का प्रयोग किया जाये। हाल ही में आई.आर. परावर्तित कूलिंग फिल्म का कम्पनियां ने किया है और कृषकों के बीच इसका चलन बढ़ा है।

यू.वी. स्टेबलाइजेशन पैकेज्ड - पोलीथीन की आयु बढ़ाने के लिए एंव उसे बिखरने से बचाने के लिए कुछ महंगे रसायनिक तत्वों को पोलीमर्स में मिलाया जाता है। परन्तु इसके प्रोसेसिग क्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। साथ-साथ पोलीफिल्म को पैरा बैगनी किरणों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के यू.वी. स्टेबलाइजेशन पैकेजज् इस्तेमाल में लिए जाते है।

1. **एच.ए.एल.एस. -** यह एक प्रकार की नवीनतम तकनीक है। इससे बनी फिल्म रगंहीन ट्रॉस लूसेंट, यू.वी. किरणों से पोली फिल्म को बचाती है और बहुतायत रूप से पी.ए. आर को अन्दर आने देती है। एच. ए. एल.एस. का मतलब हिडंरड़ अमाइन लाईट स्टेबलाइजर होता है।
2. **नीकल कूवेंचर, एच.ए.एल.एस.,** यू.वी. सोखने वाला उपरोक्त पोली फिल्म आमतौर पर हरापन लिये हुए या पीले रंग की होती है। जिन फसलों में रोग एवं कीट प्रबन्धन के लिए सल्फर, कलोरीन, है लोजन जैसे रसायनों का इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह इस पोलीथीन फिल्म का उपयोग करना चाहिए/ इस उपरोक्त गुणों की वजह से इसे सल्फर प्रति रोधी फिल्म के नाम से भी जाना जाता है।
3. **एन. ओ. आर.-एच.ए.एल.एस. -** यह एच.ए.एल.एस की पॉचवी जनरेसन है। इससे बनी पोलीथीन रंगहीन एंव कृषि में काम में लिए जाने वाले द्यातक रसायनिक तत्वों के असर से पोलीफिल्म को बचाती है। यह एक नवीनतम परन्तु एक महंगी तकनीक है। यह फिल्म सूर्य की किरणों को बिना प्रकाश की गुणवता को प्रभावित करतें हुए हरितगृह के अन्दर प्रवेष कराता है।

थर्मल डिग्रेडेशन /फोटो आक्सीडेशन - पोली हाऊस में काम से ली गई पोली फिल्म आक्सीजन एवं आद्रता लिए हए वातावरण के बीच धातु से बने ढांचे के सम्पर्क में आती है और पोलीफिल्म को क्षति पहुॅचाती है। जिसे हम आक्सीडेसन की क्रिया कहते है।

इसके अलावा पोलीहाऊस का ढ़ाचा जो की लोहे या स्टील की धातु से बना होता है। सूर्य की तेज गर्मी से गर्म हो जाता है। और जो पोली फिल्म उसके सम्पर्क में आती है। वहां से कमजोर पड़ जाती है। और धीरे-धीरे फटने लगती है इस प्रक्रिया को हम थर्मल डिग्रेडेशन कहते है।

आक्सीडेशन एवं थर्मल डीग्रेडेशन की प्रक्रिया को कम करने के लिए आक्सीडेसन प्रतिरोधी एवं थर्मल स्टेबलाइर्जस तत्वों को पोली फिल्म का उत्पादन करते वक्त मिला दिया जाता है। साथ ही कृषकों को यह हिदायत दी जाती है कि जहां तक हो सके पोली फिल्म एवं हरित गृह के ढांचे का आपस में सीधा सम्पर्क ना हो। इससे पोली फिल्म की आयु बढ़ती है।

ढ़ाचा ही नही पोली फिल्म भी है महत्वपूर्ण

आयात की गई ज्यादातर पोली फिल्म बहुपरत एवं बहुगुणो वाली होती है।

बाहरी परत	**धूल प्रतिरोधी ऋन फ्रा रेड कूलिंग**
मध्य वाली परत	**डिफ्यूजन**
अंदर वाली परत	**इनटीड्रीप इनफ्राथमिर्क**

यु वी स्टेबलाइजर, पी.ए.आर. फिल्टर, सल्फर प्रतिरोधी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एवं थर्मल स्टेबलाइजर को प्रत्येक परत में एक निश्चित मात्रा में मिलाना आवश्यक होता है ताकि पोली फिल्म अपने आप में समस्त गुणो का समावेश रख सके एवं बिना फटे एक निश्चित समय सीमा तक चल सके जिसकी गारंटी आमतौर पर पोली फिल्म निर्माता अपने उत्पादों के लिए अपने ग्राहको को देता है। बहुआयामी पोली थीन की परतों में से अगर किसी एक परत मे यह पद्धार्थ डाले जाये तो ऐसी पोली फिल्म से रिजल्ट की परिकल्पना करना व्यर्थ है।

सूर्य की किरणों को तीन भागों में बॉटा जा सकता है- यू. वी, पी. ए. आर. एवं आई. आर.। कृषि सम्बन्धित क्रियाओं में उपरोक्त सूर्य की किरणों को समझना एवं नियंत्रित करना अति आवश्यक है।

यु.वी.सी	**190 से 280 नैनो मीटर**
यू.वी.बी	**280 से 320 नैनो मीटर**
यू.वी. ए.	**320 से 400 नैनो मीटर**
पी.ए. आर	**380 से 700 नैनो मीटर**
एन. आई. आर	**700 से 1100 नैनो मीटर**
एफ. आई. आर	**1100 से 1600 नैनो मीटर**

1.	**यू. वी. -**	छोटी वेवलेंथ ज्यादा ऊर्जा
2.	**पी.ए. आर. -**	मध्यम वेवलेथं प्रकाश सस्लेशन के लिए उपयुक्त मध्यम ऊर्जा
3.	**आई. आर. -**	लम्बी वेवलेंथ गर्मी बढाने के लिए जिम्मेदार कम ऊर्जा

बरसात में फेफड़ो में भर सकता है गंदा पानी इग्नोर ना करें

बारिश के मौसम में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं, उन्हें निमोनिया का खतरा ज्यादा होता है। एक शोध में देखा गया है कि बरसात में निमोनिया के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इस बीमारी में फेफड़ों के अंदर पानी या पस बढ़ जाती है।

निमोनिया के लक्षण

बारिश में निमोनिया के लक्षण दिख सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो बलगम वाली खांसी, बुखार, सांस फूलना, तेज-तेज सांस लेना, सीने में भारीपन, भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टी आदि को नजरअंदाज ना करने की सलाह दी है।

कॉफी

कॉफी के अंदर कैफीन होता है, जो फायदे भी देता है। यह सांस की नली को रिलैक्स करता है और सांस फूलने से राहत देता है।

हल्दी की चाय

हल्दी में एंटी-इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये चीजें इंफेक्शन को खत्म करके छाती में दर्द से राहत देते हैं।

अदरक वाली चाय

अदरक का सेवन करने पर दर्द से राहत मिलती है। हल्दी की तरह इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रोपर्टी होती हैं। जो निमोनिया में राहत दे सकती हैं

मेथीदाना की चाय

मेथीदाना खाने से शरीर ज्यादा पसीना बहाने लगता है। इस वजह से इसकी चाय बुखार में पीने की सलाह दी जाती है। यह शरीर का तापमान कम करती है।

पेपरमिंट टी

निमोनिया की वजह से फेफड़ों में बलगम जम जाता है और खांसी होने लगती है। आप पेपरमिंट टी का सेवन करके इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और खांसी रोक सकते हैं। ●

बेहद चमत्कारिक है इस पेड़ की छाल का पानी

बीमारियां रहती हैं दूर

आपने आसपास अर्जुन का पेड़ तो आपने देखा ही होगा लेकिन क्या आप इसके गुणकारी फायदे भी जानते हैं। बहुत की कम लोग इस पेड़ के औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। अर्जुन की छाल आयुर्वेदिक औषधी मानी जाती है। कई तरह की बीमारियां दूर करने में इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। अर्जुन की छाल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए यह जबरदस्त फायदेमंद माना जाता है. इंफेक्शन, गले की खराश, सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को यह चुटकियों में ही दूर कर सकता है। आइए जानते हैं इसके जबरदस्त फायदे..।

सर्दी-खांसी

सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने में अर्जुन की छाल का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। इस छाल का पानी कंजेशन से राहत देता है और फेफड़ों को हेल्दी बनाकर उसकी कैपसिटी को बढ़ाने का काम करता है।

डायबिटीज

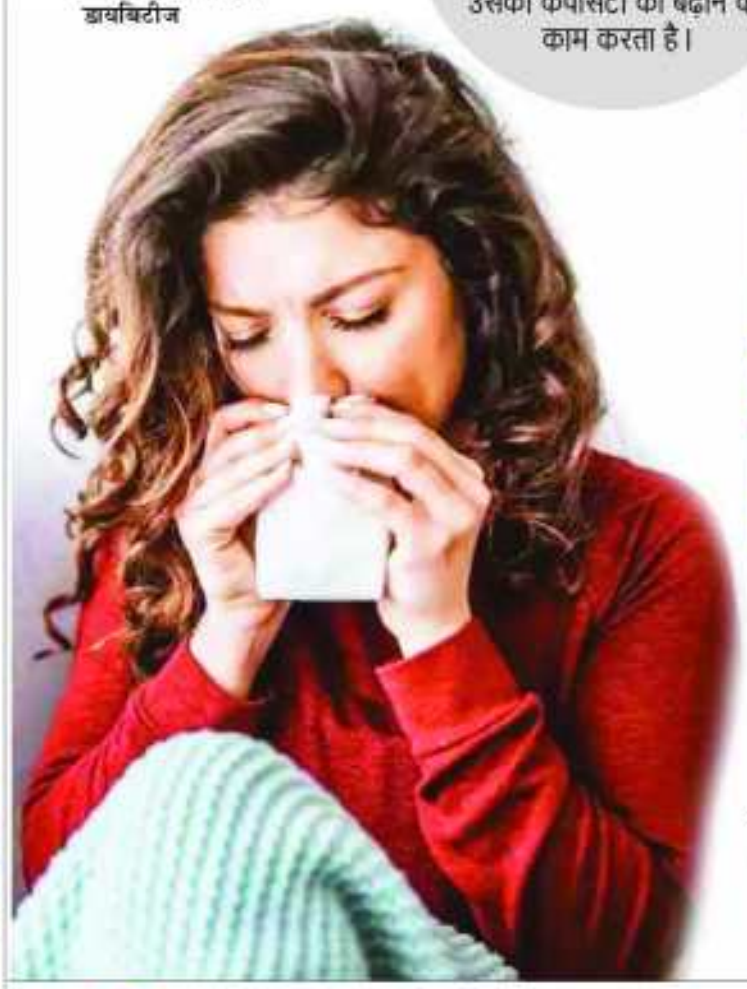

डायबिटीज कंट्रोल करने में अर्जुन की छाल का इस्तेमाल होता है। इसमें पाए जाने वाले कुछ विशेष एंजाइम्स और एंटीडायबिटिक गुण किडनी और लिवर को कैपसिटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए डायबिटीक पेशेंट को अर्जुन की छाल का पानी पीने की सलाह दी जाती है।

हार्ट डिजीज

दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में अर्जुन की छाल फायदेमंद होता है। एक शोध में पाया गया कि अर्जुन की छाल में ट्राइटरपेनॉइड नाम का खास रसायन होता है, जो हार्ट डिजीज का खतरा कम कर सकता है।

सांस संबंधी बीमारी

आर्युवेद में अर्जुन की छाल के पानी को सांस संबंधी बीमारियों के लिए काफी कारगर माना गया है। कहा जाता है कि अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों से राहत देने में यह काफी काम आ सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर

अर्जुन की छाल में ट्राइटरपेनॉइड रसायन पाया जाता है, जो हार्ट डिजीज का खतरा कम करता है। इसमें एंटीहाइपरटेंसिव गुण भी मिलते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

पाचन

अगर पाचन को बेहतर बनाना है तो अर्जुन की छाल का पानी पीना चाहिए। कब्ज और गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याओं को यह कम करने का काम करता है। इसके सेवन से पाचन मजबूत होता है। ●

हरी घास में चलने से दूर होते हैं कई विकार

सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए लोग खानपान पर ध्यान देने के साथ-साथ वर्कआउट और एक्सरसाइज भी करते हैं, पर क्या आप जानते हैं अगर आप हरी घास पर सिर्फ नंगे पांव चलते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सुबह हरी घास पर नंगे पांव चलने से सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं। बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। इस समय ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी। इस समय सूरज की किरणों से विटामिन डी आसानी से लिया जा सकता है।

- हरी घास पर नंगे पैर चलने से शरीर की ठंडक कम हो जाती है और टेंपरेचर बैलेंस में रहता है। जिससे सर्दी, कफ जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
- हरी घास पर नंगे पैर चलने से एक्युप्रेशर थेरेपी होती है। शरीर के अंग हाथ और पैरों की नसों से जुड़ी होती हैं।

जब हम नंगे पांव हरी घास पर चलते हैं तो पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है जिससे ब्लड सरकुलेशन तेज हो जाता है और ब्लॉकेज की समस्या भी दूर हो जाती है।

- हरी घास पर नंगे पांव चलने से मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। जिससे मांसपेशियों में अकड़न और दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है।
- अगर आप रोजाना हरी घास पर नंगे पांव चलते हैं तो इससे तनाव, हाइपरटेंशन, भींद की कमी, अर्थराइटिस, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
- घास पर चलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। ●

नियमित करो, बंद करो लूट का प्रभार से प्रभार का खेल

पेज 1 का शेष

जो शासकीय विभागों में खास तौर पर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों की ठेके पर भर्तीयां करने का कार्य करने लगा तो जो वर्षों से विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर पर काम कर रहे युवाओं के अनुबंधों को समाप्त कर जिसमें उन्हें 12 13 से लेकर भ्रष्टाचार के आधार पर 18000 तक वेतन का मिल रहा था उन्हीं को पुनः सेड मैप ने ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया तो उसने उन्हें कर्मचारियों को पुनः वहीं पर रखकर अकुशल न्यूनतम दैनिक मजदूरी के हिसाबसे जो कि रु. 380 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने के साथ उसमें से अपना कमीशन काटने और साथी ऊपर 18% जीएसटी का भुगतान करने के लिए भी कर्मचारी के वेतन से कटोत्रा किया। जिससे उनको वेतन भी कट पिट कर रू. 6000 मिलने लगा। जब सर्वोच्च न्यायालय .ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि जहां कर्मचारियों को 1 साल से ज्यादा के लिए नियमित कार्य करवाया जा रहा है। वहां पर ठेके और दैनिक वेतन भोगी पर नहीं रखा जा सकता उनका स्थाई रूप से भर्ती करके नियमित्त वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत प्रदेश की सरकार सभी मंत्रालयों के अधीनस्थ सभी विभागों के अंतर्गत ठेका मजदूरी से लगभग 4 लाख कर्मचारियों से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य प्रकार के कार्यों की सेवाओं में अपने ही कर्मचारियों को शोषण कर रही है जहां तक ऊर्जा विभाग की कंपनियों में जितनी भी विद्युत वितरण कंपनियां है वे सब की सब विद्युत वितरण हेतु उपभोक्ताओं की लाइनों के सुधार कार्यों, रखरखाव आदि में बिना प्रशिक्षण, सिर पर हेलमेट, हाथों में ग्लाव्ज, पाने प्लायर दिए बिना ही खंभों पर बिजली सुधार व रख-रखाव कार्यों में एसिडिटी का वह दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को चढ़ा देती है और दूसरी तरफ बिना बताए ही लोग जिन खंबों पर काम चल रहा होता है उनका विद्युत वितरण करने सूचित करने के बाद में भी ऑनलाइन चालू कर देने से प्रतिदिन 1 से 2 ठेका कर्मियों की विद्युत केस को और विद्युत के कारण अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं जब भी रिचार्ज की बात चलती है तो संबंधित अधिकारी अपने को बचाने के लिए स्पष्ट मना कर देता है कि यह हमारे यहां कार्यरत नहीं थे उसे प्रकार से उन युवा बच्चों की मौत पर उनके माता पिताओं, व पत्नि बच्चों को उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता तो यह छल कपट विद्युत कंपनियों के अधिकारी वह सरकार अपनी ही जनता का शोषण कर कब तक करते रहेंगे और अभी जो संविदा कर्मियों के लिए कार्य क्षेत्र, वेतन क्षतिपूर्ति का नीति निर्धारण किया गया है। पूरे प्रदेश भर में पूरी विद्युत कंपनियां में मुट्ठी भर संविदा कर्मी हैं। जबकि विद्युत वितरण कंपनियों की इकाइयां व उपकेंद्र गांवों तक फैले हुए हैं। जहां पर अधिकांश ठेका कर्मी पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं जिन्हें दैनिक न्यूनतम मजदूरी का वेतन के रूप मैं भुगतान किया जा रहा है जो वहां पर 10-20 सालों से लगातार कार्यरत हैं। जिन्हें तत्काल नई सरकार को नियमित्त कर्मियों के रूप में नियुक्त किया जाकर नियमित वेतनमान प्रशिक्षण के साथ सुरक्षा उपकरण दिये जाने चाहिए। जिनके दम पर ही पूरी विद्युत वितरण कंपनियां कार्य कर रही है वही सब के सब ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत यही हाल पूरे मध्यप्रदेश के सभी विभागों का है। दूसरी तरफ जो नियमित कर्मचारी अधिकारी निरीक्षक इंजीनियर डॉक्टर वर्षों से विभागों में कार्यरत हैं। उनको फर्जी सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के आधार पर क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी पद किसी भी विभाग में पदोन्नतियों को रोकने वह न करने के विरुद्ध कोई शक्ल नहीं दिया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन मंत्रजो कर्मचारी अधिकारी विभिन्न विभागों में एक बार पदोन्नत किये जाकर उच्च पदों पर पदस्थ किये गए हैं। उनको पदोवनति न करने के लिए दिया है। पर प्रदेश सरकार ने इस आधार पर जानबूझकर 20-20, 30-30 सालों से नियमित पदोन्नतियां नहीं दी जा रही है। यथार्थ में यह षड्यंत्र बिना किसी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और निर्णय के बिना जालसाजी पूर्ण तरीके से मोटा प्रभार लेकर उच्च पद का प्रभार देने के बदले मासिक वसूली के लिए यह षडयंत्र किया जा रहा है जिसे तत्काल रुक जाना चाहिए। और सभी विभागों में पदोन्नति समिति की बैठक बुला सबको स्थाई पदोन्नती कर उच्च पद प्रदान किया जाना चाहिए इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने वाले सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आते हैं। अधिकांश विभागों में लिपिक वर्गी कर्मचारियों जहां जिस पद पर भर्ती हुए थे 20-30 साल के बाद में भी बिना पदोन्नति के वहीं कार्यरत हैं और उसमें से अधिकांश एक ही पद पर भर्ती हो सेवानिवृत हुए जा रहे हैं। यही कारण है की 30 साल से भर्ती न होने के कारण वर्तमान में सभी विभागों में 20 से 30% स्टाफ रह गया और अधिकांश विभागों में समय तकनीकी और योजनाओं के बढ़ते कार्य चार गुना हो चुका है। जिसे मोहन यादव सरकार को चाहिए की तत्काल सभी विभागों की पदोन्नति समितियां की बैठकों को आहूत कर एक तरफ पुराने कर्मचारियों-अधिकारियों को तत्काल पदोन्नति करना चाहिए। तो दूसरी तरफ सभी विभागों में सभी वर्गों की अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्तियां कर सबसे पहले शासन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि एक तरफ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और दूसरी तरफ सरकार के सभी विभागों में चल रही अनेको प्रकार की योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

मप्र सरकार देश व विश्व में सबसे महंगा पेट्रोल, शराब, बिजली बेच रही

पेज 1 का शेष

जिनके लिए बाकायदा 2 से 10 गुना डीपीआर बनवाई जाती है। और ठेकों की सड़कों में ऐसी शर्ते जोड़ दी जाती हैं जिससे अधिकांश कार्य गुजराती ठेकेदारों के पास पहुंचता है और गुजराती ठेकेदारों को निर्माण कार्यों को आपने अयोध्या बनारस उज्जैन .आदि में में देखा कि किस प्रकार से वहां की सड़कें, मंदिर, कॉरिडोर, जबलपुर दिल्ली राजकोट आदि के हवाई अड्डे पुल एक ही बारिश में दम तोड़ते नजर आए। चक्की वास्तविक कार्य से उन्होंने 3से 10 गुना से ज्यादा कार्यों की भुगतान प्राप्त किया और गुणवत्ता तो जब जाहिर हो ही चुकी है यही हाल मध्य प्रदेश में जबकि अभी भी केंद्र सरकार का कार्यों की जड़ों का सन 2022 का एसओआर ही लागू है। यही कारण है की मध्य प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी परियोजना केन बेतवा परियोजना भी 35000 करोड़ की है। हाटपिपलिया लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन 6000 करोड़ की है जल संसाधन और नर्मदा घाटी में लगभग वर्तमान में डेढ़ लाख करोड़ की ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही है इनका मूल उद्देश्य तीन से 10 गुना की डीपीआर बनवाकर ठेके देने के समय ही सीधा 10 से 15% तक कमीशन हजम कर लिया जाए। सीएम राइज स्कूलों महाविद्यालयों में भी यही नौटंकी चल रही है वहां पर भी बने बने 5 से 10 साल पुराने नवनिर्माणों को भी तोड़कर पुनः नए निर्माण करने में मोटे कमीशन के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। जिसका सीधा उदाहरण नंदा नगर में एक सीएम राइज का स्कूल सन 2016-17 में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन मंजिल व छत का बनाया गया। पर वहां कभी शिक्षण कार्य नहीं हुआ क्योंकि वह स्कूल इंदौर विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों द्वारा शिक्षा विभाग को अपनी लूट डकैती और भ्रष्टाचार को छुपाने सौंपा ही नहीं गया। 5-7 साल तक स्कूल खड़ा रहा उसमें पूर्णता का प्रमाण पत्र ही नहीं दिया।

यथार्थ मैं वह स्कूल एक मंजिल छत का बनाया गया था। सच्चाई की पोल खुल जाने के इस डर से शिक्षा विभाग को सौपा ही नहीं गया। अब पुनः तोड़ दिया गया है और पुनः नया निर्माण कार्य शुरू कर दिया। चुकी भाई स्कूल हमारे मित्र बसंत गहलोत के मकान के सामने हैं। जब उन्होंने उसका सच जानने ठेकेदार से बातचीत करने का प्रयास किया तो ठेकेदार व उसके गुंडो द्वारा वहां तैनात चौकीदार ने घुसने नहीं दिया और ना ही कोई जानकारी दी साथ ही ठेकेदार के नेता मित्रों द्वारा लगातार डराने धमकाने के प्रयास किये। यह एक नमूना है। जो पूरे मध्य प्रदेश में हर विभाग के मोती दलाली और भ्रष्टाचार के हर कार्य में किया जा रहा है।

इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार अपने राजस्व आय का एक बड़ा हिस्सा इन जानकारी को करवाने के नाम पर हजम कर कर्ज पर कर्ज लेती चली जा रही है और 390 हजार करोड़ के कर्ज के बाद में भी धनाभाव बता कर फिर 88540 करोड़ का नया कर्ज लिया जा रहा है।

इसके विपरीत प्रदेश की सच्चाई यह भी है कि पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल गैस जिस पर 27% वेट और 5-6 प्रकार के सेस या अधिभार जिसमें 2-2% स्वास्थ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा और विद्यालयों का निर्माण, सड़क के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सरकारी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा व मुफ्त मध्यान्ह भोजन, कृषि आदि पर जनता पर ठोक कर वसूली जा रहे हैं। यही हाल देश व दुनिया में सबसे महंगी शराब की दारू के बावजूद शराब माफिया स्वयं मुख्यमंत्री है ऊपर भी 5 से 15% प्रति बोतल वसूल रहा है। और शिवराज से लेकर अभी तक प्रतिवर्ष इस प्रकार शराब पर ज्यादा वसूली में लगभग 20 से 50000 करोड रुपए तक की ज्यादा वसूली होती है पर यहां पर ना तो शिवराज पर मुकदमा चलाया गया और ना मोहन यादव पर चलाया जाएगा जबकि 100 करोड़ के आरोप में केजरीवाल को पिछले 3 महीने से केवल आने वाले दिल्ली चुनाव में वह प्रचार ना कर सके, के लिए बहाने पर ईडी ने अंदर कर रखा है और उसके बाद में अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि प्रदेश में यह शराब घोटाला पिछले 20 सालों से सतत चल रहा है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। यही हाल संपत्तियों की बिक्री पर लगने वाले पूरे देश भर में 4% छूट को प्रदेश में 12% तक वसूल किया जा रहा है। के बाद में भी 2से 10-20% उन हरामखोर उप पन्जीयकों को अलग से चाहिए। परिवहन में भी जहां केंद्र ने 200 ढाई सौ रुपए वहां चलाके के निर्धारित किए हैं मध्य प्रदेश में ढाई हजार वाहन अंतरण रु.1000 की जगह 10000 लिए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकारी चिकित्सालयों में भी भारी मोटी वसूली हर इलाज, जांच की, शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। जब जनता से इतनी लूट की जा रही है तो आखिर पैसा कहां जा रहा है? पूरे देश भर में यादव सरकार अपने भ्रष्टाचार लूट डकैती छुपाने हर दिन सैंकड़ों करोड़ के 2 से 4 पेज के विज्ञापन समाचार पत्रों में, 10-20 मिनीट तक के विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार व अन्य चैनलों पर दे रही है। अब यदि 3000 करोड रुपए प्रति माह विज्ञापनों पर ही खर्च किया जाएगा तो 36000 करोड रुपए साल के विज्ञापनों के खर्चे से अर्थव्यवस्था घाटी में जाएगी दूसरी तरफ जब सभी पूरे प्रदेश के लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, निगम पालिकाएं परिषदों, ग्रामीण विकास विभाग आदि में, आपने ठेके दिए हैं। कार्य करवाया है। तो पिछले सितंबर से पहले विधानसभा बाद में 10 मार्च 24 से, लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के नाम पर विभागों के नियमित निर्माण रखरखाव आदि के भुगतानों के लिए धन ही नहीं दिया और 5 जून को आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रदेश में बारिश शुरू हो गई।

पूर्व में बोला जाता रहा की सरकार के पास धन ही नहीं है तो सरकार को प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ राज्य माल एवं सेवा कर, पंजीयन, शराब, परिवहन, खनन, बिजली, प्रदेश के राज्य के राजमार्गों पर टोल टैक्स क्योंकि अधिकांश सड़क डकैती निगम की सड़कों परलिए गए कर्ज से ज्यादा वसूली हो चुकी है और सारा धन अब मध्य प्रदेश सरकार के पास आ रहा है तो वह कहां जा रहा है इसका हिसाब भी दो और घोर भ्रष्ट, जालसाज, हरामखोर मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों प्रशासनिक अधिकारियों विभागीय संचालक प्रमुख अभियंता आयुक्तजो मोती वसूली कर रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही जानबूझकर जनता को भ्रमित बनाए रखने पिछले 19 सालों से सूचना का अधिकार अधिनियम में सभी मंत्रालयों के सभी विभागों की किसी भी विभागीय साइट पर धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारी इसीलिए नहीं डाली जाती है ताकि उनके भ्रष्टाचार की कहानी को जनता देख और समझ ना सके और वह अपनी लूटपाट भ्रष्टाचार और षड्यंत्र को आसानी से छुपा कर जन धन से लूटा जा रहा सभी प्रकार का कर वसूल करने के बाद में भी कर्ज लेकर घी पीकर तान कर सोते रहें।

इजरायल पर 48 घंटे में ईरान बोलेगा हमला...

इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है। लेकिन अब ईरान के साथ भी इजरायल के तनाव बढ़ गए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वह इजरायल पर हमला करेगा। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 24-48 घंटे में ईरान पर इजरायल हमला कर सकता है। ईरान अगले 24 से 48 घंटे के बीच इजरायल पर हमला कर सकता है। यह खतरनाक दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक विशेष रिपोर्ट में किया गया है। इसमें कहा गया है कि इजरायल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में एक व्यक्ति का हवाला दिया गया जिसे ईरानी शासन नेतृत्व की ओर से जानकारी दी गई थी। इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि हमले की योजनाओं पर चर्चा की गई है। यह हमला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के जवाब में होगा, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और सदस्य मारे गए थे। इस हमले के बाद से ईरान ने इजरायल को सीधे हमले की चेतावनी दी थी। इससे पहले पिछले बुधवार को ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिका और सहयोगियों ने भविष्यवाणी की थी कि इजरायल पर तुरंत ईरान का हमला हो सकता है। एं० ने एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि हमला इजरायल की सीमाओं के अंदर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस सप्ताह की शुरुआत में IRGC ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से संपर्क किया था और उन्हें इजरायली हितों पर हमला करने का विकल्प बताया था।

इजरायल को डराने के लिए IRGC से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने हाल के घंटों में ईरान के उत्तर में हाइफा एयरपोर्ट और दक्षिण में इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना में हमले से जुड़ा एक सिमुलेटेड वीडियो पोस्ट दिया। हालांकि ईरान को इजरायल की ओर से होने वाली कड़ी कार्रवाई की भी चिंता है। रिपोर्ट में खामेनेई की चिंताओं का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक हमला उल्टा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इजरायल ईरानी मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। इसके बाद वह ईरान के बुनियादी ढांचों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। एक सलाहकार ने कहा कि वह अभी भी राजनीतिक जोखिम का आकलन कर रहे हैं। इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी ईरानी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने गुरुवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजरायल हाई अलर्ट पर और पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा इजरायल ने ईरान के साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान के हमले से अमेरिका भी अलर्ट है। अमेरिका ने इजारयल में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों से कहा है कि वे ईरानी खतरे के बीच तेल अवीव, यरूशलेम और बेर्शेबा से बाहर यात्रा न करें। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेता ईरान को संघर्ष न बढ़ाने को कह रहे हैं।

भानगढ़ सड़क का हाल-बेहाल

सड़क पर अतिक्रमण और पार्किंग से राहगीर परेशान

जिम्मेदारों की अनदेखी और थकेली रफ्तार से चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण भानगढ़ रोड की कॉलोनी में रहने वाले लोग हर दिन आते- जाते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। निगम ने सड़क का एक हिस्सा तो बना दिया है। परंतु इस पर सड़क पर लोग अवैध पार्किंग और दुकान वालों ने कब्जा कर रखा है। और तो और मैरिज गार्डन वाले की भी पार्किंग इसी सड़क पर होती है। यातायात विभाग वाहन उठाने और नगर निगम द्वारा सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है और रहवासी इनसे त्रस्त हैं।

एमआर- 10 चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा से भानगढ़ तक की सड़क का कार्य लगभग डेढ़ वर्ष से कछुआ गति से चल रहा है। इस रास्ते पर आधी-अधूरी, खुदी हुई सड़क और उस पर भी चौपहिया वाहन, ट्रक, बस, ईट भट्ठों की गाड़ियां जैसे वाहनों का आधी से ज्यादा सड़क पर कब्जा यहां 'करेला और नीम चढ़ा' वाली कहावत चरितार्थ करता है। कई बार समस्या बताने के बाद भी यातायात विभाग और इंदौर नगर निगम पूरी तरह से नजर अंदाज कर रहा है। यातायात पुलिस इस क्षेत्र से पूरी तरह नदारद है, जिससे वाहन मालिकों ने बेखौफ रास्ता रोककर सड़क को पार्किंग बना लिया है। सार्वजनिक रास्ते पर वाहनों की पार्किंग से बाद सड़क पर महज थोड़ी सी ही जगह बचती है, जिससे आम राहगीर और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में यह दिक्कत और भी बढ़ गई है। ठेकेदार द्वारा भरी लापरवाही बरती जा रही है। बड़े बड़े गड्ढों पर भी पेचवर्क नही किया जा रहा है। शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। सड़क पर जगह-जगह कई दुकानें हैं और इन दूकानदारों ने सर्विस रोड और फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा ली हैं। सर्विस रोड, फुटपाथ, गटर का स्लैब, रोड का किनारा कोई भी जगह इनसे बची नहीं है।

कछुआ गति से चल रहा कार्य

निर्माणाधीन सड़क का कार्य कछुआ गति की चाल से चल रहा है। कभी कार्य होता दिखाई देता है तो कब कार्य बंद हो जाए भगवान भरोसे है। रहवासियों द्वारा आंदोलन के वक्त केवल आश्वासन दिया जाता है। कार्रवाई तो दूर प्रशासन सुध भी नहीं ले रहा, ऐसे में सरकार को टैक्स चुकाने वाली जनता अपने आप को असहाय व ठगा हुआ महसूस कर रही है।

महिलाएं एवं स्कूली बच्चों को ज्यादा परेशानी

खराब सड़क और बची कुची सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण सबसे ज्यादा कामकाजी महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क दिखाई नहीं पड़ती इस कारण दुर्घटना का अंदेशा रहता है। स्कूल भी शुरू हो चुके हैं जिस कारण कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस, ऑटो का आना जान बना रहता है। ऊबड़ खाबड़ सड़क के कारण ऑटो में बैठे बच्चों को हर वक्त डर बैठा रहता है। स्कूल बसों के ड्रायवर भी इधर आने से कतराते हैं।

कचरा गिराते जाते है कचरा वाहन

इस सड़क पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी है जहां शहर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से छोटी गाड़ियों द्वारा कचरा एकत्रित कर यहां लाया जाता है। यहां से बड़ी गाड़ियों से देवगुराड़ियां स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाया जाता है। निगम ने यह ट्रांसफर स्टेशन इसलिए बनाया था, ताकि कम समय में शहर का कचरा एकत्रित हो सके। निगम ने इसे बना तो दिया है पर यहां ध्यान नहीं दे रहा। लगातार उपेक्षा के अभाव में यह बदहाल है। हालत यह है कि खराब सड़क के चलते इस ट्रांसफर स्टेशन पर आने वाली कचरा गाड़ियों की भी हालत खस्ता हो रही है। सड़क इतनी खुदी हुई है कि कचरे से भरी गाड़ियां पूरी सड़क पर कचरा बिखरते जाती है। जिससे आसपास के रहवासी भी परेशान हैं।

रहवासी कई बार कर चुके आंदोलन

भानगढ़ सड़क की समस्या को लेकर स्थानीय रहवासी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। रहवासियों ने हनुमान चालिसा तक का पाठ कर नेताओं और अधिकारियों को जगाने का प्रयास भी किया। परंतु किसी भी नेता-अधिकारी के सिर में जूं तक नहीं रेंगी। सड़क की हालत इतनी खराब है कि राहगीरों खासकर महिलाएं और बच्चों को हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। आए दिन कोई न कोई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल होता है।

विश्व में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत समाप्त

पेज 1 का शेष

पचास साल आगे बढ़ते हुए, और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्राप्त प्रमुख वैश्विक स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो गई है। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 1960 में 40 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गया है। चीन की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गई है। अब इसे तेजी से मुखर होते बीजिंग के साथ प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है, जबकि यूरोप और अन्य जगहों जैसे सहयोगियों द्वारा भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है जो वित्तीय और विदेश नीति के मामलों में वाशिंगटन से अधिक स्वायत्त बनना चाहते हैं। विशेष रूप से, कई देशों ने वाशिंगटन द्वारा आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बढ़ते उपयोग के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने के लिए डॉलर के लिए वैकल्पिक सीमा पार भुगतान व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी तेल पर बहुत कम निर्भर हो गया है। वास्तव में, शेल क्रांति के लिए धन्यवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और शुद्ध निर्यातक है। यह अभी भी सऊदी अरब से तेल आयात करता है, लेकिन काफी कम मात्रा में। इसके विपरीत, चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन गया है, जो राज्य के तेल निर्यात का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। बीजिंग ने पूरे मध्य पूर्व में घनिष्ठ, व्यापार-संचालित संबंध स्थापित किए हैं, जहां अमेरिकी प्रभाव कम हो गया है। सऊदी अरब की अपने तेल को बेचने में उपयोग की जाने वाली मुद्राओं में विविधता लाने की इच्छा एक बड़ी रणनीति के साथ संरेखित होती है जिसके लिए देश को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से परे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उभरते देशों के ब्रिक्स क्लब में शामिल होने और सीमा पार भुगतान के लिए अपने-अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के उपयोग का पता लगाने के लिए एमब्रिज परियोजना में चीन और अन्य देशों के साथ साझेदारी करने की किंगडम की इच्छा आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए।

डॉलर की वैश्विक दुविधा

मुद्रा विविधीकरण में सऊदी अरब की रुचि, डी-डॉलरीकरण की दिशा में एक छोटा लेकिन प्रतीकात्मक कदम है। तेजी से, देश सीमा पार व्यापार और निवेश लेनदेन में अपनी मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किसी भी प्रमुख शक्ति के प्रभाव से पूरी तरह बाहर हैं। इसमें भाग लेने वाले केंद्रीय बैंकों के बीच सहमत मुद्रा-स्वैप लाइनें और राष्ट्रीय भुगतान और निपटान प्रणालियों को जोड़ना शामिल है। सीमा पार भुगतान के लिए स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने से वर्तमान में दक्षता लागत आती है, क्योंकि यह बिना किसी वाहन के स्थानीय मुद्राओं के जोड़े का सीधे आदान-प्रदान करने के लिए कम तरल स्थानीय विदेशी मुद्रा, धन और हेजिंग बाजारों पर निर्भर करता है। ऊपर वर्णित कई देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इस लागत को आवश्यक माना है। डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कि टोकनाइजेशन, ऐसी लागतों को बहुत कम कर देगा। पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने विनिमय की 'टोकनीकरण' इकाइयों जैसे कि सीबीडीसी या डॉलर या किसी भी प्रमुख मुद्राओं से जुड़े स्थिर

सिक्के, एक संदर्भ परिसंपत्ति से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी आदि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन टोकन वाली इकाइयों को वाणिज्यिक बैंकों जैसे मध्यस्थों के खातों के माध्यम से संसाधित किए बिना तुरंत और सीधे एक्सचेंज किया जा सकता है। टोकन वाली मुद्राएँ अभी भी व्यापक रूप से अपनाए जाने से बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिभागियों को पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए भंडार रखने की आवश्यकता को काफी कम कर देगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्त में डॉलर की प्रमुख स्थिति के समर्थन के प्रमुख स्तंभ के रूप में गहरे और तरल अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूति बाजार की भूमिका कमजोर हो जाएगी। वास्तव में, वैश्विक भंडार में डॉलर का हिस्सा पहले ही 1999 में 71 प्रतिशत से गिरकर वर्तमान में 58.4 प्रतिशत हो गया है - कई माध्यमिक मुद्राओं के पक्ष में। निकट भविष्य में, डॉलर का प्रभुत्व बना रहेगा। लेकिन वैश्विक वित्तीय परिदृश्य का क्रमिक लोकतंत्रीकरण चल रहा है, जिससे एक ऐसी दुनिया का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए अधिक स्थानीय मुद्राओं का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी दुनिया में, डॉलर प्रमुख बना रहेगा, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं होगा, चीनी रेनमिनबी, यूरो और जापानी येन जैसी मुद्राएँ उसे पूरक होंगी, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न के अनुरूप होंगी। इस संदर्भ में, सऊदी अरब पेट्रोडॉलर को किस तरह से अपनाता है, यह आने वाले वित्तीय भविष्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसका निर्माण पचास साल पहले हुआ था।

साप्ताहिक समय माया

एक तरफ वृक्षों की कटाई, बागों व वनों को उजाड़ने का षड़यंत्र

51 लाख वृक्षारोपण के नाम मोटी चंदा वसूली, जनधन की बर्बादी

इंदौर में ही एमओजी लाइंस के, मल्हार आश्रम के, शहर में सतत नगर निगम द्वारा बाग बगीचों से लेकर सड़कों के किनारे लगे हजारों वृक्षों को काटने का षड़यंत्र सतत चल रहा है। जबकि जनता के साथ गैर सरकारी संगठन जनहित, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके विपरीत नए भवन, सड़कें, बांयी सड़क चौड़ी करने बनाने, स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन परियोजना लाने बनाने के अंतर्गत लाखों पेड़ों की अनाधुंध कटाई की जा रही है।

दूसरी तरफ वर्तमान के सरकार के शहरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 51 लाख पेड़ लगाने की सरकारी घोषणा जनधन से की। जैसा की इतिहास रहा है। इसकी आड़ में जैन, अग्रवाल, ब्राह्मण बनिए, पोरवाल, राजपूत व अन्य सभी समाजों, अधिकारियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, शापिंग माल्स, व्यवसायिक फर्मों, माफियाओं से सहयोग रूपी चंदा मांगने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? यथार्थ में 51 लाख वृक्षों के रोपण के नाम पर चंदा ही बटोरना मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। लाखों वृक्ष मोटे कमीशन की कीमत पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल व अन्य स्थानों से लाएंगे। जो सौ डेढ़ सौ से लेकर आगे 500 रु. 700 प्रति वृक्ष और उसका लाने ले जाने का खर्च भी सरकार के खाते से वसूला जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश वन विभाग, निगम, उद्यानिकी की नर्सरियां ऐसे पौधे 14 से 40 रुपए में इंदौर में व प्रदेश में ही बैंच रही हैं।55 लाख पौधे लगाने की आड़ मेंखर्चे से 10 गुना ज्यादा पैसा पूंजीपतियों उद्योगपतियों दुकानदारों व्यवसाईयों से बसूला जा रहा है।

दूसरी तरफ वही खर्च शहरीय विकास के हरियाली के खाते में डालकर भी अरबो रुपए हजम किया जाएगा।

तीसरा 51 लाख पेड़ लगाने की भूमि ही नहीं है। यह बात सभी समाचार पत्र छाप चुके हैं 11 लाख भी लग जाएं। और एक लाख भी जीवित रहकर 2 साल बाद भी हरियाली बिखेर दें। तो इंदौर की जनता धन्य हो जाए।

चौथा यथार्थ में वृक्षारोपण से वृक्ष बढ़ाने की कोई ठोस गारंटी नहीं।क्योंकि वृक्ष लगाना ही सारा सच नहीं वृक्ष लगाने के बाद उनकी नियमित देख भाल और सिंचाई भी आवश्यक होती है। और 51 लाख का सफलता के साथ पूरा गया किया गया की पूरी ऊपर फर्जी रिपोर्ट कर देने के बाद उनमें साल भर पानी कौन देगा? 51 लाख वृक्षों में प्रतिदिन पानी देने के लिए लगभग 51000 कर्मचारी चाहिए।

मंत्री का सरकारी कार्यक्रम है, तो जनता, समाजों व्यापारियों उद्योगों से सहयोग व वसूली क्यों?

उनका वेतन कौन देगा? और जब उनके लिए 51000 कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है, तो इंदौर कैसे हरा भरा होगा हरी भरी तो बस केवल मंत्री और भेड़िया झुंड पार्टी के नेताओं की होगी

प्रकृति सक्षम है। वह स्वयं अपना जंगल खड़ा कर लेती है। बस जरूरत इस बात की है की धरती के सबसे लालची हब्सी ढीठ निकम्मे छल कपट करने वाले मूर्ख मनुष्य नाम के प्राणी का व हरियाली चरने वाले पशुओं का उसे क्षेत्र में प्रवेश न हो केवल साल 2 साल तक उस क्षेत्र को चारों तरफ से तार लगाकर बाड़ा बंदी कर छोड़ दीजिए। वहां दो- तीन साल में घास के साथ अपने आप अनेकों प्रकार के वृक्षों का हरियली युक्त जंगल खड़ा हो जाएगा। आप भले ही वहां सिंचाई करें या ना करेंपर वृक्ष प्राकृतिक तरीके से अपने आप एक विकसित होकरचार-पांच साल मेंबड़े बच्चों के साथ आपको वन भी नजर आएगा।

यह ज्ञान मुझे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से ही प्राप्त हुआ।

पिछले 5-7 सालों से यह अनुभव कर रहा हूं। की यही प्रकृति का प्राकृतिक सच है। तो फिर 51 लाख पौधे खरीदने पर रु.100 प्रति पौधे के हिसाब से 51 करोड रु फिर प्रति पौधा लगाने में1 फीट गड्ढा खोदने वृक्षारोपण करने में अगर रु. 100 का खर्च भी आया तो 51 करोड रु वृक्षारोपण में चाहिए। वृक्षारोपण में नाम कमायेंगे मंत्री और उसके गिरोह के लोग। पैसा तो जनता का ही खर्च होगा और आपने देख लिया एक एक तरफ से ज्यादा रुपए के बिल नगर निगम में लगे जाएंगे बाजार से वसूली की जाएगीऔर खर्च नहीं किया जाएगा 10 से 15 करोड रुपए भी बाकी सब हजम। खेल समझिए।

क्या नीट में पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ है?

पेपर लीक की जांच के बीच खुला चौंकाने वाला पुराना राज

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एनटीए की नीट यूजी परीक्षा पास करना जरूरी है. इसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की लिस्ट में रखा गया है. नीट यूजी परीक्षा के जरिए लाखों की भीड़ में से टॉप कैंडिडेट्स को चुना जाता है. लेकिन अब यह परीक्षा और इसे आयोजित करवाने वाली एजेंसी यानी एनटीए जांच के घेरे में है. बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 05 मई को हुई थी. नीट यूजी पेपर लीक हो जाने की वजह से यह अब तक चर्चा में है.

नीट यूजी पेपर लीक स्कैम की जांच कई राज्यों में चल रही है. लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन-कौन शामिल है आदि. नीट स्कैम की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है नीट यूजी पेपर लीक मामले में हर दिन नई परतें खुल रही हैं. ऐसे में अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पहले भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान कोई धांधली हुई है?

नीट के दूसरे अटेंप्ट में हुआ चमत्कार

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कुछ स्टूडेंट्स को नीट यूजी के दूसरे अटेंप्ट में शानदार रैंक मिली थी. एक कैंडिडेट ने साल 2022 में हुई नीट यूजी परीक्षा में 6 डिजिट में रैंक हासिल की थी (2 लाख प्लस). 2023 में जब उसी कैंडिडेट ने दूसरा अटेंप्ट दिया तो उसकी रैंक 8000 थी और उसे मुंबई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया. अन्य कैंडिडेट की 2022 में 10 लाख से ज्यादा रैंक थी और 2023 में 13000.

क्या सच में सेकंड टाइम लक काम करता है?

ऐसे कई मामले हैं, जिनमें पहले और दूसरे अटेंप्ट की रैंक में काफी अंतर है. कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कैंडिडेट की मेहनत और भाग्य का फल है. लेकिन इन मामलों में कुछ कॉमन है- इन सभी के परीक्षा केंद्र. दरअसल, इन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी एग्जाम का सेकंड अटेंप्ट दूर-दराज स्थित परीक्षा केंद्र में दिया था. कोई नीट परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र से बेलगावी तक गया, किसी ने बिहार का छोटा सा जिला चुना तो किसी ने उन इलाकों से एग्जाम दिया, जहां कोचिंग सेंटर्स नहीं थे.

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958